



वैश्वीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के बदलते स्वरूप: एक वर्णनात्मक अध्ययन

**सन्त कुमार शुक्ल, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट (उ०प्र०)-210204**

**डॉ. सुशील कुमार त्रिपाठी, शोध निर्देशक, अध्यक्ष: राजनीति विज्ञान विभाग
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ०प्र०)-210204**

सारांश

वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, उत्पादन प्रणाली, व्यापार, निवेश, सेवा क्षेत्र तथा रोजगार के स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। विशेष रूप से आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक बाजार से संपर्क बढ़ा तथा विदेशी निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर विकसित हुए। इक्कीसवीं शताब्दी में डिजिटल तकनीक, ई-वाणिज्य, ऑनलाइन सेवाओं, स्टार्टअप संस्कृति तथा प्लेटफॉर्म आधारित कार्य के विस्तार ने अर्थव्यवस्था और रोजगार के स्वरूप को और अधिक परिवर्तित किया है। परिणामस्वरूप परंपरागत नियमित रोजगार के साथ अस्थायी, अनुबंध आधारित, स्वतंत्र तथा गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य के नए रूप सामने आए हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य वैश्वीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के बदलते स्वरूप का वर्णनात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में आर्थिक उदारीकरण, विदेशी निवेश, सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कौशल विकास, स्वरोजगार, स्टार्टअप तथा गिग और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार जैसे प्रमुख आयामों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही रोजगार की गुणवत्ता, असंगठित क्षेत्र, कौशल-असमानता, सामाजिक सुरक्षा तथा युवाओं के लिए रोजगार संबंधी चुनौतियों पर भी विचार किया गया है।

अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसके लिए सरकारी रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षणों, श्रम एवं रोजगार संबंधी आँकड़ों, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा विभिन्न संस्थागत अध्ययनों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, किंतु इन अवसरों का लाभ सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक वर्गों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। बदलती अर्थव्यवस्था में रोजगार की प्रकृति अधिक तकनीक-आधारित, कौशल-प्रधान और लचीली हुई है। अतः वैश्वीकरण से प्राप्त आर्थिक अवसरों को समावेशी बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द: वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र, कौशल विकास, गिग अर्थव्यवस्था, प्लेटफॉर्म रोजगार, स्वरोजगार।

1. प्रस्तावना

वैश्वीकरण समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, निवेश, उत्पादन, तकनीक, सेवाओं और श्रम संबंधी संपर्कों में व्यापक वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ने के साथ उत्पादन एवं रोजगार की प्रकृति को भी प्रभावित किया है। आज किसी देश की आर्थिक गतिविधियाँ केवल उसकी राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वैश्विक बाजार, तकनीक, पूँजी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती हैं।

भारत में वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु हैं। भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा से संबंधित आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और



वैश्वीकरण से संबंधित आर्थिक सुधारों को अपनाया। इन सुधारों के अंतर्गत व्यापार संबंधी प्रतिबंधों में कमी, निजी क्षेत्र को अधिक अवसर, विदेशी निवेश के प्रति अपेक्षाकृत खुली नीति तथा औद्योगिक नियंत्रणों में परिवर्तन जैसे कदम उठाए गए। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण बढ़ा।

आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई दिए। विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के साथ सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों के विकास ने भारत को वैश्विक सेवा बाजार में विशेष पहचान प्रदान की। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और अन्य शहरी केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक सेवा उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए। इन क्षेत्रों ने शिक्षित एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित श्रम के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए।

वैश्वीकरण का रोजगार पर प्रभाव केवल रोजगार की संख्या तक सीमित नहीं है। इससे रोजगार की प्रकृति और कार्य पद्धति में भी परिवर्तन आया है। पारंपरिक कृषि एवं विनिर्माण आधारित रोजगार के साथ सेवा आधारित, तकनीकी, डिजिटल और ज्ञान आधारित रोजगार का महत्त्व बढ़ा है। कंपनियों में स्थायी रोजगार के अतिरिक्त अनुबंध आधारित कार्य, आउटसोर्सिंग, स्वतंत्र पेशेवर कार्य और परियोजना आधारित रोजगार के स्वरूप भी विकसित हुए हैं।

वर्तमान समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने इस परिवर्तन को और अधिक तीव्र किया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, ई-वाणिज्य, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और ऐप आधारित प्लेटफॉर्मों के विस्तार से उत्पादन, व्यापार और सेवाओं के संचालन की पद्धति बदल रही है। डिजिटल तकनीक ने छोटे उद्यमियों एवं स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए भी नए बाजारों तक पहुँचने की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। इसी क्रम में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था रोजगार के एक नए स्वरूप के रूप में उभरी है।

गिग अर्थव्यवस्था में कार्य प्रायः अल्पकालिक, कार्य-आधारित अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्राप्त होता है। परिवहन, वस्तु वितरण, ऑनलाइन पेशेवर सेवाओं तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में इस प्रकार के रोजगार का विस्तार देखा जा सकता है। इससे श्रमिकों को कार्य संबंधी लचीलापन और आय अर्जित करने के नए अवसर मिल सकते हैं। दूसरी ओर रोजगार की स्थिरता, नियमित आय, कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न भी सामने आते हैं। वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन के कारण श्रम बाजार में कौशल का महत्त्व भी बढ़ा है। आधुनिक उद्योग और सेवा क्षेत्र में डिजिटल ज्ञान, तकनीकी दक्षता, संचार कौशल और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता की मांग बढ़ रही है। इससे कौशल विकास रोजगार नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जिन युवाओं के पास बाजार की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा एवं कौशल उपलब्ध हैं, उनके लिए नए अवसर विकसित होते हैं, जबकि कौशल की कमी रोजगार प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों का व्यापक अस्तित्व है। इसलिए वैश्वीकरण से उत्पन्न आर्थिक विकास को केवल उच्च तकनीकी एवं आधुनिक सेवा क्षेत्रों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। बड़ी संख्या में श्रमिक कृषि, छोटे व्यवसाय, निर्माण, घरेलू कार्य तथा अन्य असंगठित गतिविधियों में कार्यरत हैं। इनके लिए रोजगार की सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय युवाओं की रोजगार संबंधी आकांक्षाओं में भी परिवर्तन आया है। सरकारी एवं परंपरागत निजी नौकरियों के साथ स्टार्टअप, उद्यमिता, फ्रीलांस कार्य, ऑनलाइन सेवाएँ तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार नए विकल्पों के रूप में सामने आए हैं। इससे रोजगार की अवधारणा नौकरी प्राप्त करने तक सीमित न रहकर स्वरोजगार एवं उद्यमिता तक विस्तृत हुई है। हालांकि इन अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए पूँजी, तकनीक, कौशल और डिजिटल संसाधनों तक पहुँच आवश्यक होती है।

इस प्रकार वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ है। एक ओर इसने विदेशी निवेश, व्यापार, तकनीकी विकास, सेवा क्षेत्र और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित किया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार की गुणवत्ता, कौशल-असमानता, असंगठित श्रम, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विषमता जैसी चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं।

अतः वर्तमान संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण को केवल आर्थिक वृद्धि के आधार पर न देखा जाए, बल्कि यह भी समझा जाए कि आर्थिक परिवर्तन रोजगार की प्रकृति और श्रमिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध-पत्र वैश्वीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के बदलते स्वरूप का वर्णनात्मक अध्ययन करता है।



2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. वैश्वीकरण के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप का अध्ययन करना।
2. वैश्वीकरण के कारण भारतीय रोजगार संरचना में आए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णनात्मक विश्लेषण करना।
3. सेवा क्षेत्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार और रोजगार के बीच संबंध का अध्ययन करना।
4. डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार से उत्पन्न रोजगार के नए स्वरूपों का अध्ययन करना।
5. भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार की उभरती प्रवृत्ति का वर्णनात्मक विश्लेषण करना।
6. वैश्वीकरण के संदर्भ में युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमिता की भूमिका का अध्ययन करना।
7. वैश्वीकरण से उत्पन्न रोजगार संबंधी अवसरों एवं प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना।
8. गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों को रेखांकित करना।

3. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र की प्रकृति **वर्णनात्मक (Descriptive)** है। अध्ययन का उद्देश्य वैश्वीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार संरचना में आए प्रमुख परिवर्तनों का उपलब्ध तथ्यों और अध्ययनों के आधार पर व्यवस्थित वर्णन एवं विश्लेषण करना है। अध्ययन में किसी विशिष्ट कारणात्मक संबंध को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित करने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार में दिखाई देने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास किया गया है।

यह अध्ययन मुख्यतः **द्वितीयक आँकड़ों एवं स्रोतों** पर आधारित है। इसके लिए भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित प्रकाशनों, नीति आयोग की रिपोर्टें, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशनों, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा अन्य प्रामाणिक संस्थागत अध्ययनों का उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन की विषय-वस्तु को प्रमुख रूप से आर्थिक परिवर्तन, सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, रोजगार संरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, गिग एवं प्लेटफॉर्म रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार संबंधी चुनौतियों जैसे विषयगत आयामों में विभाजित किया गया है। उपलब्ध सामग्री का इन आयामों के आधार पर वर्णनात्मक विश्लेषण किया जाएगा।

अध्ययन मुख्य रूप से समकालीन भारतीय परिदृश्य पर केंद्रित है। अतः वर्तमान आर्थिक एवं रोजगार संबंधी प्रवृत्तियों के विश्लेषण में यथासंभव **2021 से 2026 के मध्य प्रकाशित नवीन स्रोतों और आँकड़ों** को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों का उल्लेख केवल वर्तमान वैश्वीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए किया गया है।

4. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप

वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय बाजार का वैश्विक अर्थव्यवस्था से संपर्क बढ़ा और व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीकी हस्तांतरण तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में विस्तार हुआ। इस परिवर्तन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनाया। वैश्विक अर्थव्यवस्था से बढ़ते जुड़ाव के कारण भारतीय उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र को नए बाजार प्राप्त हुए, वहीं घरेलू उद्यमों के सामने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती भी बढ़ी।

भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान नहीं रहा है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर इसके प्रभाव की प्रकृति अलग-अलग दिखाई देती है। विशेष रूप से सेवा क्षेत्र ने वैश्वीकरण के दौर में तीव्र विस्तार किया।



सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा व्यावसायिक सेवाओं के विस्तार ने अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आए इस परिवर्तन ने रोजगार संरचना को भी प्रभावित किया। कृषि पर निर्भर रोजगार के साथ उद्योग एवं सेवा आधारित रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हालांकि रोजगार संरचना का परिवर्तन आर्थिक उत्पादन की संरचना में आए परिवर्तन के समान गति से नहीं हुआ है। कृषि आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के बीच संतुलन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

वैश्वीकरण के वर्तमान चरण में डिजिटल तकनीक आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख आधार बन गई है। ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल भुगतान, ई-वाणिज्य, डिजिटल सेवाएँ तथा तकनीक आधारित उद्यम आर्थिक गतिविधियों के नए स्वरूप विकसित कर रहे हैं। इस कारण वैश्वीकरण और डिजिटल परिवर्तन के बीच संबंध अधिक गहरा हुआ है।

5. सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विस्तार

भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में देखा जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण, अंग्रेजी भाषा में दक्ष मानव संसाधन, तकनीकी शिक्षा तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार ने भारत को वैश्विक सेवा बाजार से जुड़ने में सहायता प्रदान की।

सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ने भारत में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए। सॉफ्टवेयर विकास, डेटा प्रबंधन, ग्राहक सहायता, वित्तीय सेवाएँ, डिजिटल मार्केटिंग और तकनीकी परामर्श जैसे कार्यों के विस्तार से शिक्षित एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएँ बढ़ीं। इसके परिणामस्वरूप बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई जैसे शहरी केंद्र आधुनिक सेवा एवं तकनीकी रोजगार के महत्वपूर्ण केंद्र बने।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि इसने भारतीय श्रम बाजार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कार्य से जोड़ा। किसी भारतीय शहर में बैठा कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पेशेवर दूसरे देश में स्थित संस्था के लिए सेवा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार कार्य और कार्यस्थल के पारंपरिक संबंध में परिवर्तन आया है।

कोविड-19 महामारी के बाद दूरस्थ एवं हाइब्रिड कार्य प्रणालियों की स्वीकार्यता ने इस परिवर्तन को और स्पष्ट किया। डिजिटल संचार तकनीकों के माध्यम से अनेक प्रकार के पेशेवर कार्य कार्यालय से बाहर रहकर भी किए जाने लगे। इससे कार्यस्थल की भौगोलिक सीमाएँ अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हुई हैं।

हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को अधिक प्राप्त होता है जिनके पास आवश्यक शिक्षा, तकनीकी कौशल और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। इस कारण तकनीकी विकास के साथ कौशल संबंधी असमानता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

6. भारतीय रोजगार संरचना में परिवर्तन

वैश्वीकरण ने भारत में रोजगार के अवसरों के साथ रोजगार की प्रकृति को भी प्रभावित किया है। पहले रोजगार की सामान्य धारणा स्थायी नौकरी, निश्चित कार्यस्थल और नियमित कार्य समय से अधिक जुड़ी हुई थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था में इसके साथ अनुबंध आधारित, परियोजना आधारित, अस्थायी, फ्रीलांस, दूरस्थ और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य के स्वरूप विकसित हुए हैं।

6.1 कृषि से गैर-कृषि रोजगार की ओर परिवर्तन

भारतीय अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से कृषि प्रधान रही है। आर्थिक विकास के साथ उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों का विस्तार हुआ है और गैर-कृषि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। निर्माण, परिवहन, व्यापार, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं ने श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं।

इसके बावजूद कृषि का रोजगार में महत्व बना हुआ है। यह स्थिति संकेत करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन अभी जारी है। कृषि से बाहर आने वाले श्रमिकों के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण गैर-कृषि रोजगार उपलब्ध कराना भविष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

6.2 नियमित रोजगार के साथ लचीले रोजगार का विस्तार

वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी परिवर्तन के कारण संस्थाएँ अपने कार्यबल के प्रबंधन में अधिक लचीले मॉडल अपना रही हैं। अनुबंध आधारित रोजगार, आउटसोर्सिंग और परियोजना आधारित कार्य इसी परिवर्तन का हिस्सा हैं। ऐसे रोजगार से संस्थाओं को आवश्यकतानुसार श्रम प्राप्त करने की सुविधा होती है और श्रमिकों के लिए नए अवसर भी



उत्पन्न होते हैं।

दूसरी ओर लचीले रोजगार के साथ रोजगार की स्थिरता, नियमित आय और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए रोजगार के नए स्वरूपों का मूल्यांकन केवल रोजगार की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता के आधार पर भी किया जाना आवश्यक है।

6.3 महिलाओं के लिए रोजगार के बदलते अवसर

वैश्वीकरण और डिजिटल तकनीक ने महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए क्षेत्रों का विस्तार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-वाणिज्य, ऑनलाइन सेवाएँ और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के नए अवसर विकसित हुए हैं।

घर से कार्य, ऑनलाइन उद्यमिता और डिजिटल माध्यमों से व्यवसाय संचालित करने की सुविधा कुछ महिलाओं के लिए कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में सहायक हो सकती है। किंतु महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी केवल रोजगार उपलब्ध होने से निर्धारित नहीं होती। शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक मान्यताएँ, देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ और कार्यस्थल की परिस्थितियाँ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

7. डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर

वर्तमान समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था भारतीय आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम बन गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से आशय उन आर्थिक गतिविधियों से है जिनमें इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा, डिजिटल भुगतान और सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

डिजिटल भुगतान प्रणालियों के प्रसार ने छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच आर्थिक लेन-देन की पद्धति को बदला है। ई-वाणिज्य ने उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए स्थानीय बाजार से बाहर उपभोक्ताओं तक पहुँचने की संभावना विकसित की है। इसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षा, परामर्श, डिजाइन, लेखन, तकनीकी सहायता और अन्य डिजिटल सेवाओं ने स्वतंत्र पेशेवर कार्य के अवसर उत्पन्न किए हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोटे एवं मध्यम उद्यमों पर भी दिखाई देता है। डिजिटल मंचों के माध्यम से छोटे उद्यम अपने उत्पादों का प्रचार, भुगतान और बिक्री कर सकते हैं। इससे बाजार तक पहुँच की लागत कम होने और नए ग्राहकों से जुड़ने की संभावना उत्पन्न होती है।

इसके बावजूद डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए इंटरनेट, उपकरण, डिजिटल साक्षरता और आवश्यक कौशल की जरूरत होती है। इसलिए डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ डिजिटल विभाजन रोजगार संबंधी असमानता को भी प्रभावित कर सकता है।

8. गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का उदय

भारतीय श्रम बाजार में गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य रोजगार के उभरते स्वरूपों में से एक है। गिग कार्य में व्यक्ति किसी संस्था के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने के बजाय विशिष्ट कार्य अथवा सीमित अवधि के आधार पर अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। जब इस प्रकार के कार्य को डिजिटल मंच के माध्यम से श्रमिक और ग्राहक के बीच व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार कहा जाता है।

परिवहन, वस्तुओं की डिलीवरी, घरेलू सेवाओं, डिजाइन, लेखन, तकनीकी सेवाओं, परामर्श तथा स्वतंत्र पेशेवर कार्य जैसे अनेक क्षेत्रों में गिग आधारित कार्य दिखाई देता है। स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान ने इस प्रकार के कार्य के विस्तार के लिए आवश्यक आधार उपलब्ध कराया है।

8.1 गिग अर्थव्यवस्था के अवसर

गिग अर्थव्यवस्था का प्रमुख लाभ कार्य संबंधी लचीलापन है। व्यक्ति अपनी उपलब्धता के अनुसार कार्य चुन सकता है और कुछ परिस्थितियों में एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित कर सकता है। युवाओं, विद्यार्थियों, स्वतंत्र पेशेवरों और अतिरिक्त आय की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए यह रोजगार का वैकल्पिक माध्यम हो सकता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे शहरों में रहने वाले कुशल व्यक्तियों को भी व्यापक बाजार से जोड़ सकते हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन किए जा सकने वाले कार्यों में भौगोलिक स्थान की बाधा कम हो सकती है।

8.2 गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

गिग और प्लेटफॉर्म रोजगार के साथ अनेक श्रम संबंधी प्रश्न भी जुड़े हैं। नियमित वेतन, रोजगार की स्थिरता, स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा, अवकाश, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ पारंपरिक नियमित रोजगार की तुलना में सीमित हो



सकते हैं।

प्लेटफॉर्म द्वारा कार्य का आवंटन, रेटिंग प्रणाली और आय निर्धारण भी श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए गिग अर्थव्यवस्था के विकास के साथ श्रमिक अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा का उपयुक्त ढाँचा विकसित करना आवश्यक है।

9. युवा वर्ग, कौशल विकास और बदलता रोजगार बाजार

भारत की युवा जनसंख्या आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। किंतु युवा जनसंख्या का आर्थिक लाभ अभी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षा और कौशल रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन ने कौशल की प्रकृति में व्यापक बदलाव किया है।

9.1 कौशल की बदलती माँग

आज रोजगार बाजार में केवल औपचारिक शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं मानी जाती। डिजिटल साक्षरता, तकनीकी कौशल, संचार क्षमता, समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक सोच और नई तकनीक सीखने की क्षमता का महत्व बढ़ रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, क्लाउड तकनीक और स्वचालन जैसी तकनीकों के विस्तार के कारण अनेक कार्यों की प्रकृति बदल रही है। इसलिए कार्यरत व्यक्तियों को भी समय-समय पर अपने कौशल को अद्यतन करने की आवश्यकता बढ़ी है।

9.2 कौशल-असमानता की चुनौती

तकनीकी एवं उच्च कौशल वाले रोजगार के विस्तार का लाभ सभी युवाओं को समान रूप से प्राप्त नहीं होता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण, इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों तक पहुँच में अंतर कौशल-असमानता उत्पन्न करता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, विभिन्न आय समूहों तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच उपलब्ध अवसरों का अंतर भी रोजगार परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार बाजार से उसके संबंध को मजबूत करना होना चाहिए।

10. स्वरोजगार, स्टार्टअप एवं उद्यमिता

वैश्वीकरण के दौर में रोजगार की अवधारणा केवल वेतन आधारित नौकरी तक सीमित नहीं रह गई है। स्वरोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता को भी रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। डिजिटल तकनीक ने छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने और उसे व्यापक बाजार तक पहुँचाने की संभावनाएँ बढ़ाई हैं।

सोशल मीडिया, ई-वाणिज्य और डिजिटल भुगतान ने नए उद्यमियों के लिए विपणन और लेन-देन को अपेक्षाकृत सरल बनाया है। कोई छोटा उत्पादक या सेवा प्रदाता डिजिटल माध्यम से अपने क्षेत्र से बाहर भी ग्राहक प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार डिजिटल सामग्री निर्माण, ऑनलाइन शिक्षण, डिजाइन, परामर्श और अन्य पेशेवर सेवाओं में स्वरोजगार की संभावनाएँ विकसित हुई हैं।

स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं में नौकरी प्राप्त करने के साथ रोजगार उत्पन्न करने की अवधारणा को भी प्रोत्साहित किया है। नवाचार और तकनीक आधारित उद्यम नए उत्पाद एवं सेवाएँ विकसित करने के साथ रोजगार सृजन में योगदान कर सकते हैं।

हालांकि उद्यमिता के लिए केवल नवीन विचार पर्याप्त नहीं है। वित्तीय संसाधन, बाजार की जानकारी, तकनीकी क्षमता, व्यावसायिक कौशल और संस्थागत सहायता भी आवश्यक होती है। इसलिए स्वरोजगार और स्टार्टअप को रोजगार नीति के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करते समय इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

11. वैश्वीकरण और रोजगार के सकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय श्रम बाजार में अनेक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार ने नए प्रकार के रोजगार उत्पन्न किए हैं। वैश्विक बाजार से जुड़ाव ने तकनीकी और पेशेवर सेवाओं के निर्यात के अवसर बढ़ाए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने स्वरोजगार, फ्रीलांस और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य के नए माध्यम विकसित किए हैं।

तकनीकी हस्तांतरण एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने आधुनिक कौशल की आवश्यकता को बढ़ाया है, जिससे शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। युवाओं के सामने परंपरागत नौकरियों के अतिरिक्त उद्यमिता और डिजिटल सेवाओं के विकल्प भी उपलब्ध हुए हैं।



वैश्वीकरण ने भारतीय पेशेवरों को अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार से जुड़ने में भी सहायता प्रदान की है। सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य ज्ञान आधारित सेवाओं में भारतीय मानव संसाधन की वैश्विक उपस्थिति इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है।

12. वैश्वीकरण और रोजगार से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

वैश्वीकरण के आर्थिक लाभों के बावजूद भारतीय रोजगार बाजार के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। पहली चुनौती पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार उत्पन्न करने की है। आर्थिक वृद्धि तभी व्यापक सामाजिक विकास का माध्यम बन सकती है जब उससे स्थिर और सम्मानजनक रोजगार भी उत्पन्न हों।

दूसरी चुनौती असंगठित रोजगार की व्यापकता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को नियमित आय, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएँ सीमित रूप में उपलब्ध हो सकती हैं।

तीसरी चुनौती कौशल और रोजगार के बीच असंगति है। शिक्षा प्राप्त युवाओं की योग्यता और उद्योगों द्वारा अपेक्षित कौशल के बीच अंतर होने पर रोजगार उपलब्ध होने के बावजूद उपयुक्त श्रमिक मिलने तथा युवाओं को उपयुक्त नौकरी प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है।

चौथी चुनौती तकनीकी परिवर्तन से संबंधित है। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ नियमित कार्यों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं, वहीं नए कौशल आधारित कार्य भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए तकनीक को केवल रोजगार समाप्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना उचित नहीं है। वास्तविक चुनौती श्रमिकों को बदलती तकनीक के अनुरूप तैयार करने की है।

पाँचवीं चुनौती रोजगार में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानता की है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार तक पहुँच समान नहीं है। अतः वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों को समावेशी बनाने के लिए रोजगार नीति में क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

अंततः गिग एवं प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार के विस्तार ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नए प्रश्न उत्पन्न किए हैं। भविष्य की रोजगार नीति में इस बढ़ते कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा और उचित कार्य परिस्थितियों से जोड़ना महत्वपूर्ण होगा।

13. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

प्रस्तुत वर्णनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार की संरचना में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक बाजार, विदेशी निवेश, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ाव बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर विकसित हुए हैं तथा रोजगार की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं—

1. **भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण बढ़ा है।** उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने व्यापार, निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और निजी क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित किया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक बाजार में भागीदारी बढ़ी है।
2. **सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है।** सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संचार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के विस्तार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी एवं बीपीओ क्षेत्र ने भारत को वैश्विक सेवा बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3. **रोजगार के स्वरूप में विविधता आई है।** परंपरागत नियमित रोजगार के साथ अनुबंध आधारित, अस्थायी, परियोजना आधारित, फ्रीलांस, दूरस्थ तथा प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार के नए रूप विकसित हुए हैं। इससे रोजगार की पारंपरिक अवधारणा में परिवर्तन आया है।
4. **डिजिटल अर्थव्यवस्था रोजगार परिवर्तन का महत्वपूर्ण आधार बन रही है।** इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, ई-वाणिज्य तथा ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने नए व्यवसाय और रोजगार अवसर उत्पन्न किए हैं। डिजिटल माध्यमों ने छोटे उद्यमियों एवं स्वतंत्र पेशेवरों को भी व्यापक बाजार से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है।
5. **गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था रोजगार के उभरते हुए स्वरूप हैं।** इनसे कार्य संबंधी लचीलापन और आय अर्जित करने के नए अवसर प्राप्त हुए हैं, किंतु रोजगार की स्थिरता, आय की नियमितता तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।



6. **युवा वर्ग के लिए कौशल का महत्त्व बढ़ा है।** तकनीक आधारित एवं वैश्विक श्रम बाजार में डिजिटल कौशल, संचार क्षमता, तकनीकी दक्षता, समस्या समाधान तथा नई तकनीकों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होती जा रही है।
7. **स्वरोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर विकसित हुए हैं।** डिजिटल मंच, ई-वाणिज्य और ऑनलाइन सेवाओं ने युवाओं एवं छोटे उद्यमियों को नए बाजार उपलब्ध कराए हैं। इससे रोजगार की अवधारणा केवल नौकरी प्राप्त करने तक सीमित न रहकर रोजगार सृजन से भी जुड़ी है।
8. **वैश्वीकरण का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है।** शिक्षा, कौशल, डिजिटल संसाधनों, पूँजी और बाजार तक पहुँच में अंतर के कारण विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समूहों के बीच रोजगार संबंधी अवसरों में असमानता बनी हुई है।
9. **रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है।** केवल रोजगार उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। नियमित आय, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा और कार्य की स्थिरता भी गुणवत्तापूर्ण रोजगार के आवश्यक आयाम हैं।
10. **तकनीकी परिवर्तन अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है।** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और अन्य नवीन तकनीकें कुछ कार्यों की प्रकृति को बदल रही हैं, वहीं नए कौशल आधारित रोजगार भी उत्पन्न कर रही हैं। इसलिए बदलते श्रम बाजार के अनुरूप कौशल विकास आवश्यक है।

समग्र रूप से अध्ययन यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को अधिक विविध, तकनीक-आधारित और वैश्विक बनाया है, किंतु इसके लाभों को व्यापक और समावेशी बनाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है।

14. सुझाव

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एवं रोजगार संबंधी अवसरों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने तथा उससे जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

प्रथम, रोजगारोन्मुख कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बदलते श्रम बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना आवश्यक है। डिजिटल कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, संचार कौशल और अन्य आधुनिक दक्षताओं के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

द्वितीय, शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाकर युवाओं को ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो वास्तविक रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

तृतीय, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियों और आधुनिक सेवा क्षेत्रों का अत्यधिक शहरी केंद्रीकरण क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ा सकता है। डिजिटल अवसररचना, स्थानीय उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करके स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित किए जाने चाहिए।

चतुर्थ, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। इस वर्ग के श्रमिकों के लिए बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना सहायता, पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों की प्रभावी पहुँच आवश्यक है।

पंचम, महिला रोजगार को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित की जानी चाहिए। सुरक्षित कार्यस्थल, परिवहन सुविधाएँ, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच तथा देखभाल संबंधी सुविधाएँ महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

षष्ठ, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को संस्थागत सहयोग दिया जाना चाहिए। युवाओं और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार संबंधी जानकारी तथा डिजिटल मंचों तक पहुँच उपलब्ध कराना आवश्यक है। इससे रोजगार खोजने वाले युवाओं को रोजगार सृजित करने की दिशा में भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।



सप्तम, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रमिकों का पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच, कौशल उन्नयन तथा उचित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

अष्टम, तकनीकी परिवर्तन के अनुरूप पुनःकौशल एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तकनीक में तेजी से होने वाले परिवर्तन के कारण केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। कार्यरत श्रमिकों को भी समय-समय पर नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

नवम, रोजगार नीति में केवल रोजगार की संख्या के बजाय रोजगार की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्थिर आय, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ समावेशी आर्थिक विकास के आवश्यक तत्व हैं।

दशम, वैश्वीकरण से प्राप्त अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा, तकनीक, कौशल और बाजार तक बेहतर पहुँच प्रदान करके आर्थिक विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

15. निष्कर्ष

वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं रोजगार संरचना को नई दिशा प्रदान की है। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत का वैश्विक व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सेवा बाजार से जुड़ाव बढ़ा। इस प्रक्रिया ने एक ओर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया, तो दूसरी ओर भारतीय श्रम बाजार की प्रकृति में भी परिवर्तन उत्पन्न किया। सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास इस परिवर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है।

वर्तमान समय में वैश्वीकरण का आर्थिक स्वरूप डिजिटल परिवर्तन से और अधिक जुड़ गया है। इंटरनेट, ई-वाणिज्य, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने उत्पादन, व्यापार और रोजगार के नए स्वरूप विकसित किए हैं। नियमित रोजगार के साथ फ्रीलांस, दूरस्थ, गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य का विस्तार यह दर्शाता है कि रोजगार की पारंपरिक अवधारणा निरंतर परिवर्तित हो रही है।

इन परिवर्तनों ने विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं। तकनीकी एवं डिजिटल कौशल रखने वाले युवा अब स्थानीय बाजार के साथ राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उपलब्ध रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जुड़ सकते हैं। स्टार्टअप और उद्यमिता ने भी रोजगार संबंधी संभावनाओं को विस्तृत किया है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने रोजगार को केवल नौकरी प्राप्त करने की अवधारणा से आगे बढ़ाकर कौशल, नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता से भी जोड़ा है।

इसके बावजूद वैश्वीकरण के आर्थिक लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँचे हैं। कौशल-असमानता, असंगठित रोजगार, क्षेत्रीय विषमता, रोजगार की गुणवत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य ने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, किंतु इनसे श्रमिकों की आय सुरक्षा, कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नए प्रश्न भी उत्पन्न हुए हैं।

तकनीकी परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के संदर्भ में रोजगार का भविष्य भी महत्वपूर्ण विषय बन गया है। नई तकनीकें कुछ परंपरागत कार्यों को परिवर्तित कर सकती हैं, किंतु इसके साथ नए प्रकार के कौशल एवं रोजगार की माँग भी उत्पन्न होती है। इसलिए तकनीकी परिवर्तन का सामना करने के लिए शिक्षा, पुनःकौशल और कौशल उन्नयन को निरंतर प्रक्रिया के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

अतः वैश्वीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए केवल आर्थिक वृद्धि का माध्यम मानना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आर्थिक विकास किस सीमा तक **गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और समावेशी रोजगार** उत्पन्न करता है। रोजगारोन्मुख कौशल विकास, डिजिटल समावेशन, महिला एवं युवा भागीदारी, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देकर वैश्वीकरण से प्राप्त आर्थिक अवसरों को अधिक व्यापक सामाजिक लाभ में परिवर्तित किया जा सकता है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। भविष्य की आवश्यकता इन परिवर्तनों को रोकने की नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी नीतियों के माध्यम से दिशा देने की है जिनसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा के साथ सामाजिक न्याय, रोजगार की गुणवत्ता और समावेशी



विकास भी सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2026)। *आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 (Economic Survey 2025-26)*। नई दिल्ली: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2026)। *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS): मासिक बुलेटिन, जून 2026*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।
3. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2026)। *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS): त्रैमासिक बुलेटिन, अक्टूबर-दिसंबर 2025*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।
4. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2026)। *वित्तीय वर्ष 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान एवं चौथी तिमाही के जीडीपी अनुमान*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।
5. भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) (2025)। *भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट, 2025 (State of India's Digital Economy Report 2025)*। नई दिल्ली: ICRIER-Prosus Centre for Internet and Digital Economy।
6. नैसकॉम (2025)। *वार्षिक रणनीतिक समीक्षा 2025 (Annual Strategic Review 2025)*। नई दिल्ली: National Association of Software and Service Companies (NASSCOM)।
7. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2025)। *आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 (Economic Survey 2024-25)*। नई दिल्ली: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
8. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2025)। *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS): वार्षिक रिपोर्ट, जुलाई 2023-जून 2024*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक (2025)। *वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 (Annual Report 2024-25)*। मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक।
10. भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2025)। *वार्षिक रिपोर्ट 2024-25*। नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।
11. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान (2024)। *भारत रोजगार रिपोर्ट 2024: युवा रोजगार, शिक्षा एवं कौशल (India Employment Report 2024: Youth Employment, Education and Skills)*। नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान।
12. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2024)। *आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 (Economic Survey 2023-24)*। नई दिल्ली: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
13. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2024)। *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS): वार्षिक रिपोर्ट, जुलाई 2022-जून 2023*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।
14. मिश्रा, डी., केडिया, एम., रेड्डी, ए., रामनाथ, के. एवं मनीष, एम. (2024)। *भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट, 2024 (State of India's Digital Economy Report 2024)*। नई दिल्ली: भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER)।
15. रेड्डी, ए., केडिया, एम. एवं शुक्ला, एस. (2024)। *भारत में डिजिटल भुगतान का प्रसार: फोनपे पल्स के आँकड़ों पर आधारित अध्ययन (Diffusion of Digital Payments in India: Insights Based on Data from PhonePe Pulse)*। नई दिल्ली: भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER)।



16. भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (2024)। *वार्षिक रिपोर्ट 2023-24*। नई दिल्ली: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार।
17. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2023)। *आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 (Economic Survey 2022-23)*। नई दिल्ली: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
18. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2023)। *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS): वार्षिक रिपोर्ट, जुलाई 2021-जून 2022*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।
19. भारतीय रिज़र्व बैंक (2023)। *वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 (Annual Report 2022-23)*। मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक।
20. नीति आयोग (2022)। *भारत की उभरती गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: कार्य के भविष्य पर दृष्टिकोण एवं सुझाव (India's Booming Gig and Platform Economy: Perspectives and Recommendations on the Future of Work)*। नई दिल्ली: नीति आयोग, भारत सरकार।

